Rupali Choubey

Paper - II - Part A

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

1 (a) रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

- ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित के लिए यह एक्ट लाया गया
- प्रावधान - कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना
- बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, बंगाल, मद्रास का गवर्नर जनरल माना

(B) बी. एन. राव

भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कहे जाते
- इनके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार जिसका प्रारूप समिति ने विचार-विमर्श कर्मों के संविधान का प्रारूप तैयार

(C) अनु. 39(A)

- भाग 4, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित
- समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची

- भाषाओं भारतीय भाषाओं के संबंध में प्रावधान
- प्रारंभ में 14 भाषायें व वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।

(ख) एल. एम. सिंघवी

- पंचायती राज्य से संबंधित समिति
- स्थापना – 1986
- सिफारिशें → स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही

(ग) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- यह बर्लिन (जर्मनी) में स्थित
- करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता
- भारत की स्थिति इस सूचकांक में – 80th

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

(a) लोक अदालत

- सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर गठित
- यह न्यायालय में लंबित मामलों व दाखिल मामलों की शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी सहमति से मामलों को सुलझाती
- लोक अदालत न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) + 1 वकील + 1 सामाजिक कार्यकर्ता होता

(b) केंद्रीय सूचना आयोग

- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के द्वारा आयोग का गठन
- संरचना → 1 अध्यक्ष + 10 से अधिक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
- कार्य → जनता को शासन प्रशासन के निर्णयों व कार्यों तक पहुँच सुनिश्चित करना

(c)

Scanned with CamScanner

(I) संसदीय फोरम

(J) न्यायिक समीक्षा

- इसको संविधान के मूल ढांचे में स्पष्ट उल्लेख किया गया
- इसके अंतर्गत सुप्रीम व उच्च न्यायालय सरकार की विधि की समीक्षा कर असंवैधानिक घोषित कर सकता (संविधान के विरोध में)

(K) धन्यवाद प्रस्ताव

- संसदीय व्यवस्था से संबंधित
- इसके अंतर्गत प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र व वित्तीय वर्ष के पहले सत्र राष्ट्रपति सदन को संबोधित
- इसमें राष्ट्रपति सरकार की पूर्ववर्ती व आने वाले वर्ष की नीतियों व योजनाओं बताता
- दोनों सदनों में चर्चा व पारित होता

Scanned with CamScanner

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या

C

मानव अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणतंत्र राज्य के ५५ वें वर्ष 8 जनवरी १९९४ को संसद द्वारा पारित
- २८ सितम्बर १९९३ को लागू

M

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी

- यह अकादमी मसूरी (उत्तराखंड) में स्थापित
- यह भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

Q 2(b) संविधान के 33 वे अनुच्छेद पर टिप्पणी लिखिये?

A

यह भारतीय संविधान के भाग-3 में मूल अधिकारों में अनु. 33 का प्रावधान किया

अनु. 33 में निम्न प्रावधान है जो इस प्रकार है -

- संसद को अधिकार होता है कि वह सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों अन्य प्रकार के मूल अधिकारों पर उचित युक्त प्रतिबन्ध लगा सके।
- इन बलों के लिए विधिनिर्माण का अधिकार संसद का होता है तथा इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है

अतः अनु. 33 सुरक्षा बलों के संबंध में मूल अधिकारों संबंधी व्यवस्था की गई ताकि इनके बीच अनुशासन बना रहे।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार
प्रश्न संख्या
मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

Q 2 (c)

वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं

भारतीय संविधान के अनु. 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था जिसमें वित्तीय स्थायित्व के संकट में राष्ट्रपति लागू करता।

वित्तीय आपातकाल के समय निम्न प्रभाव/कार्यवाहीं होते हैं

- राष्ट्रपति राज्यों व केन्द्र को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन के लिए निर्देश दे सकता है
- राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवा के सर्पेक्ट अधिकारियों के वेतन व भत्तों में कटौती (राष्ट्रपति निर्देश)
- आप ही यह निर्देश देता है कि धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु संरक्षित
- राष्ट्रपति केन्द्र सरकार के अधिकारियों के वेतन-भत्तों में कटौती के निर्देश इसमें उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल

इस तरह वित्तीय स्थायित्व के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं कि अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

2(ब) प्राक्कलन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

A

संसदीय कार्यों व सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए स्थायी समितियों की स्थापना की जाती उनमें से एक प्राक्कलन समिति एक है प्राक्कलन समिति पर नजर डालें तो इसको निम्न प्रकार से समझ सकते है

प्राक्कलन समिति

- संरचना → 30 सदस्य सभी लोकसभा के होते
- कार्य → वित्तीय जाँच
  - → अनुमानो की समीक्षा कि विधि के अनुसार है या नहीं
  - → प्रशासनिक कार्यकुशलता व मितव्ययता के लिए सुझाव
- कमियाँ — विशेषज्ञता का अभाव
  - → सुझाव पर सरकार बाध्य नहीं

इस तरह यह समिति लोक व्यय पर नियंत्रण का काम करती

Scanned with CamScanner

2(A) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित न्यायालय पर चर्चा कीजिये?

भौतिकतावादी संस्कृति में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लाया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए तीन स्तरों पर न्यायालयों की स्थापना

उपभोक्ता न्यायालय

- केन्द्र स्तर पर
- राज्य स्तर
- जिला स्तर

केन्द्र स्तर पर => इसके अंतर्गत वही मामले आते जो वस्तु या सेवा या मूल्य/दावा 1 करोड़ से अधिक से सम्बन्ध होते

राज्य स्तर पर => इसके अंतर्गत 20 लाख से 1 cr. तक के मामले आते

जिला स्तर पर => 20 लाख से कम के मामले आते है

इन न्यायालयों के विरुद्ध अपील भी वरिष्ठ न्यायालय को की जा सकती है

इस तरह प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक व उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा रहा है।

KAUTILYA ACADEMY

Scanned with CamScanner

Q 2(b) लोकतंत्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया के सकारात्मक व नकारात्मक व नकारात्मक भूमिका का वर्णन करें?

लोकतंत्र में मीडिया को चतुर्थ स्तंभ के रूप में माना जाता है जो सरकार व जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। मीडिया (इलेक्ट्रानिक मीडिया) के पहलू पर नजर डाले तो सकारात्मक भूमिका

- सरकार की योजनाओं व कार्यों को जनता के समक्ष
- जनता की मांगों व मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत
- चुनाव के समय मतदाता को जागरूक
- सरकार की नीतियों की आलोचना तथा भ्रष्टाचार के खुलासे में अहम भूमिका।
- राजनैतिक दलों के नियमों व उनके प्रोपेगेंडा को जनता के समक्ष रखना।
- देश व विदेश की सभी खबरें मीडिया के माध्यम से ही पता चलती

जहां इलेक्ट्रानिक मीडिया के लाभ वहीं कुछ कमियाँ भी है-

- मीडिया पर सरकार का प्रभाव दिखलाता
- सांप्रदायिकता बढ़ाने में
- वह निचले स्तर के लोगों की समस्याओं व मुद्दों की अनदेखी।

Scanned with CamScanner

- स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया का अभाव
- किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना व लोगों की भावनाओं को उत्तेजित

इस तरह मीडिया के जहाँ लाभ है वही कमियाँ भी नजर आती फिर भी इन कमियों को दूर कर संतुलित स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

Q 2(ग) भारतीय संविधान के संघीय तत्वों का वर्णन कीजिये

भारतीय शासन व्यवस्था संघीय प्रणाली को अपनाया जो लोकतंत्र को अधिक प्रभावित करती है

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को निम्न प्रकार से समझा जाता

संघीय तत्व

- शक्तियों का पृथक्करण
- द्विसदनीय
- द्विराज पद्धति
- संविधान की सर्वोच्चता
- अन्य

शक्तियों का पृथक्करण => केन्द्र व राज्यों के लिए शक्तियों का पृथक्करण जहाँ संघसूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची

द्विसदनीय व्यवस्था => केन्द्र में संसद में लोक सभा व राज्य सभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व

द्विराजपद्धति => केन्द्र व राज्यों की अपनी शासन व्यवस्था
- राज्यों को स्वायत्तता प्रदान

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

संविधान की सर्वोच्चता => संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है।

अन्य => स्वतंत्र न्यायपालिका
- लिखित संविधान (विस्तृत)
- कठोर संविधान जिसमें संशोधन आसान नहीं

इस तरह संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किन्तु कुछ एकात्मक तत्व भी नजर आते जो हमारे देश की एकता व अखण्डता के लिए आवश्यक।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

2(ए)

भारत व अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में भिन्नता का वर्णन

भारतीय संविधान में अनु. 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया जो अमेरिका से लिया गया है

भारत अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की तुलना की जाये तो विभिन्नता दिखायी पड़ती है जो इसप्रकार

भारत का उपराष्ट्रपति	अमेरिका का उपराष्ट्रपति
जहाँ राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उप-राष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति के पद को स्वीकार कर सकता है	वही अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के खाली होने पर शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति कार्य भार सम्भालता।

इस तरह दोनो देशो की उपराष्ट्रपति के संबंध में भिन्नता रखती जो उनके देश काल परिस्थिति के आधार पर है।

Q2 (b)

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

भारतीय संविधान में अनु. 163 में राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती जो नाममात्र का प्रधान होता है

राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्राप्त है उनमे विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त जो इस प्रकार

- राज्यपाल विधानमंडल से पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता
- यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन का अनुरोध
- वह धन विधेयक या अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के आरक्षित कर सकता है
- यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया तथा मंत्रिपरिषद उस पर विचार-विमर्श नहीं किया तो वह मुख्यमंत्री से अपेक्षा करेगा कि वह उस मामले/निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे।
- वह मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता।

इस तरह राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्राप्त की गई जो मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त जो उसके पद को गरिमापूर्ण बनाती है।

Scanned with CamScanner

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

Q4 3(ख) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण पर लेख लिखिये?

भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ महिलाओं की अवहेलना प्राचीन काल से चली आ रही है घरेलू हिंसा की घटनाएँ भी समाज में आम बात है घरेलू हिंसा का तात्पर्य महिलाओं की शारीरिक, मानसिक व लैंगिक हिंसा के रूप में लिया जाता है जो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, व सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। किंतु आधुनिक काल में महिलाओं के प्रति जागृति आई व उनकी सशक्तिकरण की बात की भारती तथा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कई संवैधानिक व वैधानिक कदम उठाए गये।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता

संवैधानिक संरक्षण	वैधानिक	अन्य
	- घरेलू संरक्षण अधिनियम, 2005	
	- दहेज निषेध अधिनियम, 1961	
	- भारतीय न्याय संहिता	

Scanned with CamScanner

संवैधानिक प्रावधान = अनु. 14 - समता का अधिकार
अनु. 15 - लिंग के आधार पर विभेद प्रतिषेध
- नीति निदेशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन (उपबन्ध)
- अनु. 46 - सामाजिक न्याय
- अन्याय व शोषण से सुरक्षा
प्रथम रूप से महिलाओं को एकावत बनाते

विधिक अधिकार => घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
जिसमें निम्न प्रावधान किये घरेलू हिंसा गये हैं -
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला स्वयं, वकील की सहायता या संरक्षण अधिकारी की सहायता से न्यायालय के समक्ष शिकायत कर सकती है।
- पीड़ित महिला स्वयं, पड़ोसी, परिवार सदस्य न्यायालय में शिकायत दायर कर सकता
- इस कानून के तहत क्षतिपूर्ति की राशि, बच्चों का संरक्षण व रहने की व्यवस्था भी की जाती
- संरक्षण अधिकारी का भी प्रावधान जिससे पीड़ित महिला सहायता ले सकती है

Scanned with CamScanner

अन्य उपाय - महिला आयोग की स्थापना केन्द्र व राज्य स्तर पर
- एन जी ओ
- सरकारी योजनाओं से महिलाओं का सशक्त कर जैसे - SHG, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि

इस तरह महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है किंतु यह सब उपाय नाकामी सिद्ध हो रहे है इसके लिए हमें समाज व नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वह युद्ध प्रवृत्ति न रहे इसके अलावा महिलाओं को जागरूक तथा सशक्त होने की आवश्यकता ताकि वह अपने अधिकारों का उपयोग कर घरेलू हिंसा से स्वयं को व अन्य महिलाओं को बचा सकती व अपराधी को दण्ड दिलवा सकती तभी समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा।

Scanned with CamScanner

Que 3(c)

राजकोषीय नीति पर वित्त मंत्रालय की भूमिका को स्पष्ट करें?

Ans

किसी भी शासन, प्रशासन को सुचारु रूप से संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है किसी देश के लिए धमनियों का काम करती है। बिना वित्त के किसी देश की शासन व्यवस्था पड़ जाती है अतः वित्त की व्यवस्था संरक्षण, नियंत्रण, मितव्ययिता के लिए एक वित्त मंत्रालय की भूमिका अहम हो जाती है जो वित्त संबंधी सभी कार्यों को संचालित करता है।

राजकोषीय नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका की बात करने से पहले हमें राजकोषीय नीति को समझना होगा।

"सरकार के राजस्व संग्रहण तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाती है।"

इस नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका निम्न प्रकार से देखा जा सकता है -

KAUTILYA ACADEMY INDORE

Scanned with CamScanner

वित्त मंत्रालय की भूमिका

वित्त का नगमे | केन्द्र सरकार | संसाधन | कर | अन्य प्रबंधन व प्रस्ताव | को वित्त | सुधार तैयार
नियंत्रण | सम्मिलित | की भूमिका

वित्त का प्रबंधन व नियंत्रण => संघ सरकार के वित्त प्रबंधन व नियंत्रण के लिये जिम्मेदार

- प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा प्राप्त अनुमानों की छान-बीन

नगमे प्रस्ताव सम्मिलित => बिना मंत्रालय की अनुमति के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं

- यदि कोई मंत्री वित्त मंत्री व कैबिनेट के निर्णय से असहमत तो वह त्यागपत्र दे देता

केन्द्र सरकार को वित्त की उपलब्धता => यह वित्त का प्रबंधन करता
- वित्तीय प्रश्नों का समाधान

संसाधन सुधार => दिशा-निर्देश से संसाधनों का सुधार (विभिन्न योजनाओं)

Scanned with CamScanner

कर लगाने व ऋण लेने के लिए नियमन

बजट तैयार => मंत्रालय के अंतर्गत अर्थ विभाग के अधीन बजट प्रभाग जो बजट तैयार करता है

वित्त की उपलब्धता =>

अन्य => चालू प्रचलित योजनाओं व नवीन योजनाओं, का अनुमान तैयार करते समय मितव्ययिता व वित्त की उपलब्धता को ध्यान में रखना।

नई योजनाओं के व्यय संबंधी जाँच-पड़ताल करता है

इस तरह वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति पर नियंत्रण व नजर रखता है ताकि जनता का धन अपव्यय न हो व देश के आर्थिक विकास व लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जाये जिससे देश की शान्ति व लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

Scanned with CamScanner